



# भारत का दातापत्र

The Gazette of India

# असाधारण EXTRAORDINARY

## આગ II-સણ્ડ 3-ઊર્ધ્વ-સણ્ડ (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८२]

नई दिल्ली, श्रावण, जून 26, 1981/ग्रामांड 5, 1903

No. 282] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 1981/ASADHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उच्चोग संदर्भालय

### (ग्रौदीगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 25 जन, 1981

क्षा० आ० ८१५ (अ) /१८/ब्र० ख्र० आ४० द्वी० आ० ८०/८१—  
केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१  
(१९५१ का ६५) की धारा १८ च व्र का उपभारा (१) के खण्ड (व्र)  
द्वारा प्रबल मक्कियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय  
(श्रीधोगिक विकास विभाग) के आदेश में १११(भ) /१८ च व्र/आ४० द्वी० आ० ८०/८१/७८, तारीख २७ जून, १९७९ (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त  
आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के गणपत्र  
में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त गेसी सभी संविवाचों, सम्पादन  
हस्तांतरण पत्रों, कागजों, व्यवस्थापनों, पत्राटों, स्थायी वार्ताओं या अन्य  
लिखितों (उनसे भिन्न जो बैंकों और विनियम संस्थाओं के प्रतिसूत शायिकों  
से संबंधित है) का प्रवर्तन जिनका मैसर्स हन्कें ट्रायर मिस्टेड, कलकत्ता  
नामक श्रीधोगिक उपक्रम या ऐसे श्रीधोगिक उपक्रम की स्वामित्व कम्पनी  
एक पक्षकार है या जो ऐसे श्रीधोगिक उपक्रम या कम्पनी को लाग द्दे,  
एक वर्ष की अवधि के लिए नियमित रेहेगा और उक्त तारीख से पूर्व  
उसके अधीन प्रवृत्त गेसी सभी प्रधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यनाम  
और बायित्व उस प्रवधि के तिरु नियमित रहेंगे ;

और उक्त प्रादेश की अवधि को 26 जून, 1941 तक, जिसमें यह दिन भी शम्भालित है, और विस्तारित किया गया था, देश्मुक्ख भरकार के उद्योग मन्त्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग) का प्रादेश सं० 470(प्र)-18 च 344०० ई० आर० ३०/८०, तारीख 27 जून, 1980 ;

प्रौर केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उसन आदेश की प्रतिधि को एक वार्ता की प्रतिरिक्षण प्रवर्धित के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए,

अत, केन्द्रीय सरकार, उद्धार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 10 च वा की उपधारा (2) द्वारा प्रत्येक राज्यों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेश की श्रवधि को 26 जून, 1982 तक जिसमें यह दिन भी मस्मिलिन है, एक वर्ष की प्रतिरक्षित श्रवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा० सं० २(२०)/८०-सी० य० ए०]

मी० के० मोदी, संग्रह अधिक

## MINISTRY OF INDUSTRY

**(Department of Industrial Development)**

## ORDER

New Delhi, the 26th June, 1981

**S.O. 515(E)/18FB/IDRA/81.**—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry

(Department of Industrial Development) No. 411(E)/18FB/IDR A/78 dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Incheck Tyres Limited, Calcutta, or the company owing such industrial undertakings is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 26th June, 1981, vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 470(E) 18FB/IDRA/80 dated the 27th June, 1980.

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year upto and inclusive of the 26th June, 1982.

[F. No. 2(20)/80-CUS]  
C. K. MODI, Jt. Secy.